Directory for 1996-97 is under publication. However company-wise coal production in the country during 1996-97 is as under:—

Company	(million tonnes) (Provisional)
ECL	29.65
BCCL	27.13
CCL	32.21
NCL	37.01
WCL	31.23
SECL	55.30
MCL	37.37
NEC	0.75
CIL	250.65
SCCL	28.73
CAPTIVE COLLIERIES (TISCO, IISCO & DVC)	6.28
TOTAL	286.66

(b) to (e) A massive welfare programme for improving the quality of life of the coal miners has been undertaken in Coal India Limited (CIL) since the post nationalisation period. Some of the achievements in this regard are as under:—

	At the time of Nationalisation	As on 1.1.97
Housing satisfaction	21.7%	62.18%
Population covered under water supply scheme	227300	2304467
Number of hospitals	49	85
Number of hospital beds	1482	5760
Number of dispensaries	197	447
Number of ambulances	42	672
Number of schools and colleges and the periphery of the coalfields getting grant-in-aid by caol companies.	287	1346
Number of canteens	210	446
Number of co-operatives	177	313

Projected demand for coal

3817. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the projected demand for coal in the country particularly in the State of Punjab by the end of Ninth Five Year plan period;

(b) whether Government propose to formulate any scheme to meet this demand in the country;

(c) if so the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) The deamand for coal in the country by the end of 9th Five Year Plan, as assessed by Working Group on coal and lignite, is 439.70 million tonnes. The demand for coal is assessed sector-wise and not state-wise. This demand includes the demand of consuming sectors in Punjab.

(b) to (d) Steps being taken to augment domestic production of coal to bridge the gap between demand and supply of coal during the 9th Five Year Plan inter-alia, include the following:

(i) Opening up of new mines and increasing efficiency and productivity in the existing mines by modernisation, application of new technologies and ensuring timely availability of inputs and infrastructural facilities.

(ii) Partial de-regualtion of coal prices which is likely to improve the generation of internal financial resources of the coal companies which will facilitate implementation of projects. It will also improve the financial viability of new mining projects.

(iii) The capital base of Coal India Limited has been restructured which will enable it to raise additional financial resources from the capital markets which are required to add new coal production capacity.

(iv) Steps are being taken in co-ordination with the Railways to remove the transportation bottlenecks in such coalfield

areas which have potential for enhanced production.

(v) Steps are being taken to remove the bottlenecks in land acquisition and forest land clearances for speedier implementation of coal projects.

(vi) Private sector companies engaged in production of iron and steel, cement and generation of power have been permitted to take up coal mining for capitive consumption. This is expected to increase domestic coal production and availability.

(vii) To attract private investment in the coal sector, Government has decided to move a Bill to make the necessary legislative changes relating to coal mining to enable any Indian company to mine coal and lignite for sale.

घरेलू कोयले की मात्रा के संबंध में अनुमान

3818. **श्री ओमप्रकाश कोहली:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय के अनुमान के अनुसार देश में कितनी मात्रा में घरेलू कोयला उपलब्ध है;

(ख) इसकी वर्तमान अनुमानित मांग कितनी है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया और उस पर रुपए तथा डालर के रूप में पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च की गई?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) चालू वर्ष अर्थात् 1997-98 हेतु कोयले की अनुमानित मांग तथा प्रक्षिप्त उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:—

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग	उत्पादन प्रेक्षपण
1997-98	323.4	298.00
	(6.8)	

(ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के कलकत्ता कार्यालय में उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए आयात तथा तत्संबंधी कीमत का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:—

(मिलियन टन में)

वर्ष	कुल आयात	कीमत (करोड़ रु० में)
1992-93	6.49	1307.54
1993-94	7.33	1415.57
1994-95	10.73	2035.69
1995-96	12.51	2690.84
1996-97 (अप्रैल, 96 से सितम्बर, 96)	6.21	1444.77

(अद्यतन अंतिम रूप दिया गया)

कोयले के उत्पादन और विपणन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

3819. **श्री ओमप्रकाश कोहली:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयले के उत्पादन और विपणन कार्य में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र (टिस्को की खानों) से 5.3 मि० टन कोयले के उत्पादन होने की संभावना है, जो कि देश के 286 मि० टन कुल कोयले के प्रक्षिप्त उत्पादन में से है। उक्त कंपनी लौह तथा इस्पात उत्पादन में ग्रहीत उपयोग हेतु कोयले का उत्पादन करती है।

(ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत विद्युत उत्पादन तथा लौह, इस्पात तथा सीमेंट उत्पादन से जुड़ी कंपनियां ग्रहीत उपभोग के लिए कोयले का उत्खनन किए जाने की भी पात्र हैं। अभी तक 19 कंपनियों को ग्रहीत कोयला ब्लाकों की पेशकश की गई हैं, जिसमें राज्य सरकारों की विद्युत उपयोगिता शामिल हैं। 9 कंपनियों ने अपनी उत्खनन योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं तथा इसमें से 5 खनन योजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है। वैधानिक अनुमोदन के अधीन प्रतिस्पर्द्धा निविदाओं के आधार पर भारतीय कंपनी को कोयले के खनन ब्लाकों को आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह से उत्खनित किए गए कोयले को खुले बाजार में बेचा जा सकता है। यह संभावना है कि आगामी वर्षों में कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाएगी।